जो दिखाई
देता है हमेशा
सच नहीं होता।
– अज्ञात

विज्ञान और टेक्नॉलजी के विकास

इस नए प्रोसेसर की मदद से नई दवाओं की खोज से लेकर शहरों का मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्ट जैसे काम आसान हो जाएंगे। सरकार ने पूरे देश में डेटा सेंटर पार्क बनाने का फैसला किया है। आंगनबाड़ी, पुलिस स्टेशन से लेकर बड़े–बड़े दफ्तरों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

अमर वर्मा।

आम बजट 2020 में एक ऐसे आधुनिक भारत के निर्माण का स्वप्न झलकता है, जो दुनिया में विकसित हो रही नवीनतम तकनीक को हर स्तर पर अपनाने में सक्षम हो। आज विज्ञान और टेक्नॉलजी के निरंतर विकास के जरिए अनेक देशों ने अभूतपूर्व तरक्की की है। वहां के नागरिकों के जीवन में आमूल बदलाव आया है। भारत में भी जीवन के हर स्तर पर नई तकनीक, नए तरीकों को अपनाने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसलिए इस बजट में तकनीक पर खास तौर से फोकस किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस संबंध में कई बड़े ऐलान किए हैं। जैसे सरकार अगले 5 सालों में क्वॉन्टम ऐप्लिकेशन पर 8 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। गौरतलब है कि क्वॉन्टम कंप्यूटिंग ऐसॉ टेक्नॉलजी है, जिसकी मदद से बड़े डेटा और इन्फॉर्मेशन को बहुत कम वक्त में प्रोसेस किया जा सकता है। इस नए प्रोसेसर की मदद से नई दवाओं की खोज से लेकर शहरों का मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्ट जैसे काम आसान हो जाएंगे। सरकार ने पूरे देश में डेटा सेंटर पार्क बनाने का फैसला किया है। आंगनबाड़ी, पुलिस स्टेशन से लेकर बड़े–बड़े दफ्तरों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। एक लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ने की योजना है।

जाहिर है, इससे ग्रामीण भारत का डिजिटलाइजेशन हो सकेगा। इसका गांव के लोगों खासकर युवाओं को काफी लाभ मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि किसान खेती के पारंपरिक तरीकों से बाहर निकलें और कृषि कार्य में भी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करें। बजट में कुसुम योजना को जारी रखने का फैसला किया गया है। इसके जरिए किसानों को अपनी जमीन में सौर ऊर्जा उपकरण और पंप लगाकर सिंचाई करने की सुविधा मिलेगी। इसकी मदद से किसान अपनी भूमि पर सोलर पैनल लगाकर इससे बनने वाली बिजली का उपयोग खेती के लिए कर सकते हैं। उनकी जमीन पर बनने वाली बिजली से देश के गांवों में बिजली की अबाध आपूर्ति शुरू की जा सकती है। उद्योग एवं व्यापार के विकास के लिए ऑनलाइन कृषि मंडी 'ई–नाम' और सरकारी खरीद पोर्टल 'जेम' के लिए 27,300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। शिक्षा का आधुनिकीकरण वर्तमान सरकार का प्रमुख लक्ष्य रहा है। सरकार जल्द नई शिक्षा नीति का ऐलान करेगी जिसके तहत देश में ऑनलाइन डिग्री लेवल प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स पर जोर दिया जाएगा और युवाओं को इस दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए लैंड बैंक की जानकारी दी जाएगी। एक पोर्टल के जरिए वे सभी जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी, जिनकी उन्हें जरूरत होती है। विज्ञान और तकनीक के विकास के लिए विश्वस्तरीय शोध, अनुसंधान और कौशल आधारित शैक्षणिक संस्थान खोले जाएंगे। इसके लिए शिक्षा में एफडीआई को बढ़ावा दिया जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि तकनीक के जरिए सामाजिक–आर्थिक बदलाव का नया रास्ता खुलेगा।

बड़ी चिंता नहीं

अशोक वोहरा। सब कुछ कर दिया! अब आप किसी को भी अपने मन पसंद निजी और संरक्षित संचार का आनंद ले सकते हैं, अपने डेटा पर झपकी लेने वाली आँखों के बारे में खुद को परेशान किए बिना।

धर्म-दर्शन

सिग्नल जैसे विकल्प सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सेवा के लिए डिफॉल्ट विकल्प हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि सुरक्षा प्लेटफॉर्म की अपनी परतें हैं, जो पहले से कहीं अधिक है। यहां तक कि अगर आप डेटा गोपनीयता को एक बड़ी चिंता नहीं मानते हैं, तो सिग्नल का अद्भुत होना जैसे कि आत्म–विनाशकारी संदेश, एन्क्रिप्शन एहसान को समाप्त करना और डेटा गोपनीयता को प्रदान करता है जो हर समय ऐप का समर्थन करता है। सिग्नल जिसे पहले टेक्स्ट सिक्योर प्राइवेट मैसेंजर कहा जाता था, संभवतः अग्रणी एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सेवा है, जो डेटा गोपनीयता के क्षेत्र में एक विशाल घूमता है।

संपादकीय

टैक्स में छूट

वित्त मंत्री ने बजट में व्यक्तिगत करदाता को टैक्स में छूट दी है। इससे सरकार को 40 हजार करोड़ रुपये की आय का नुकसान होगा। कंपनियों द्वारा देय डिविडेंड पर टैक्स आदि में छूट देने से 25 हजार करोड़ की आय में कटौती होगी। सरकार की आय में 65 हजार करोड़ रुपये की कटौती होगी। तदनुसार वित्त मंत्री ने वित्तीय घाटे में वृद्धि की है जिससे कि इस घाटे की भरपाई हो सके। जो रकम पूर्व में सरकार को टैक्स के रूप में मिलनी थी, अब उस रकम को सरकार ऋण लेकर अर्जित करेगी। इस ऋण के कारण सरकार के वित्तीय घाटे में वृद्धि होगी। सरकार की सोच है कि आयकर में कटौती से आम आदमी के हाथ की रकम में वृद्धि होगी।

इसके दो लाभ हो सकते हैं। पहला यह कि वह उस बची हुई रकम से बाजार में माल खरीदेगा जिससे बाजार में मांग बनेगी। दूसरा लाभ यह हो सकता है कि वह उस रकम को निवेश करेगा। इनमें से प्रथम प्रभाव सही दिखता है। लेकिन इससे निवेश में वृद्धि होगी इसकी संभावना लगभग नगण्य है। कारण यह कि करदाता दुकान अथवा उद्योग में निवेश तब करेगा जब बाजार में मांग होगी। इस बजट में बाजार में मांग बढ़ाने का पुट लगभग अनुपस्थित है। तदनुसार करदाता निवेश अधिक करेगा, ऐसा नहीं लगता है।

दूसरी समस्या यह है कि करदाता से आयकर में जो वसूली कम की गई उसकी भरपाई ऋण लेकर की गई है। इस ऋण का बोझ अंततः आम आदमी पर ही पड़ेगा। उस ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज सरकार को येन केन प्रकारेण टैक्स से अर्जित करना पड़ेगा। अब कंपनियों द्वारा दिए कॉरपोरेट टैक्स और व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाले व्यक्तिगत इनकम टैक्स दोनों में कटौती की जा चुकी है।

अब बार फिर चीन से एक ऐसी ही गंभीर बीमारी का जन्म हुआ है। एक ऐसा वायरस जिसकी जानकारी अब तक विज्ञान में थी ही नहीं, वो चीन में तो कहर ढा रहा है।

गंभीर बीमारी का जन्म

लिमटी खरे।

बेशक पिछले दो दशक में चीन ने दुनिया को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लेकर दवाएं और कच्चा माल निर्यात किया और अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार किया हो लेकिन इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि इन दो दशकों में चीन ने दुनिया को हजारों गंभीर बीमारी भी निर्यात की जिनसे विश्व भर हजारों लोग संक्रमित हुए और बड़ी संख्या में लोगों को मौत की नींद सुलाया। अब बार फिर चीन से एक ऐसी ही गंभीर बीमारी का जन्म हुआ है। एक ऐसा वायरस जिसकी जानकारी अब तक विज्ञान में थी ही नहीं, वो चीन में तो कहर ढा रहा है। अब ये वायरस दुनिया के कई दूसरे देशों तक भी पहुंच गया है।

हालात की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता कि चीन के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 5974 लोगों के इस वायरस के चपेट में आने की पुष्टि की जा चुकी है। इस वायरस की चपेट में आए 1239 मरीजों की हालत गंभीर है, जबकि 132 मरीजों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है इस बीमारी की शुरुआत चमगादड़ का सूप पीने से हुई है। चीन के वुहान शहर में यह सूप पीने वाली एक लड़की से कोरोना वायरस फैला है। साल 2018 में दुनिया भर में तबाही मचाने वाले निपाह

वायरस भी चमगादड से फैला था। इससे पहले, बर्ड फ्लू, सवाइन फ्लू और चिकेन पॉक्स जैसी गंभीर संक्रमित बीमारियाँ भी जानवरों का मांस खाने से ही दुनिया भर में फैल चुकी है।

इसमें कोई दोराय नहीं है कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा मांस उत्पादक देश है। इसमें हर तरह का मांस शामिल है। मच्छर के अंड़े, से लेकर छिपकली, सांप, कुत्ते का मांस, जिंदा ऑक्टोरपस, समेत कई दूसरे सीफूड और जानवरों के मांस चीन के बाजार का वर्षों से हिस्सा, रहे हैं। भले ही अजीब लगे, लेकिन चीन में बड़े चाव के साथ खाया जाता है। कुत्तों के मांस को लेकर तो यहां पर इनकी चोरी भी बड़ी आम है, लेकिन कहीं न कहीं इन जानवरों का मांस यहां के लिए अभिशाप भी साबित होता रहा है। क्योंकि कई तरह के नए वायरस पूरी दुनिया में चीन से ही फैले हैं, जिनके पीछे वजह जानवरों का मांस ही रहा है। यहां पर मांस की खपत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि चीन में मांस परोसने वाले रेस्तरां की तादाद बीते पांच वर्षों में जबरदस्त तरह से बढ़ी है।

मांसाहार से फैलने वाला यह कोरोना वायरस इंसान के फेफड़ों में घातक संक्रमण करता है. सबसे पहले संक्रमित व्यक्ति के शरीर का तापमान बढ़ जाता है यानी उसे बुखार आता है जिसके बाद उसे सूखी खांसी होती है। एक सप्ताह बाद उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। पहले व्यक्ति को सर्दी जुकाम और खांसी होती है, और फिर स्थिति गंभीर होती जाती है। हालाँकि कोरोना ऐसा पहला वायरस नहीं है जो चीन के रास्ते पूरी दुनिया में फैल रहा हो। इससे पहले वर्ष 2002 में चीन के गुआंगडांग में सार्स का वायरस पाया गया था। यहां से निकलने के बाद यह वायरस तेजी से दुनिया के दूसरे देशों में भी फैला और करीब आठ हजार लोग इसके संक्रमण की चपेट में आए थे। इस वायरस ने पूरी दुनिया में करीब 800 लोगों की जान ली थी।

साल 2012 में चीन में 774 लोगों की मौत का जिम्मेदार सार्स वायरस भी मांसाहार के कारण ही दुनिया में फैला था और तबाही मचाई थी।

अष्टयोग-4951

5		3			6	2
	31	1	25	5	33	
3		5	4		6	7
	27		28	1	37	6
2			1		5	
	36	6	37	3	35	
		4			2	

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है.खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं.गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी.सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 4950 का हल

3	7	2	5	1	6	4
6	33	1	25	5	31	3
1	7	6	2	3	4	5
5	39	4	31	6	34	7
4	7	5	3	2	6	1
2	36	7	36	7	30	2
7	1	3	5	4	2	6

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग: खराब होती छवि

मोहन। सीएए कानून को बनाने वालों ने सोचा होगा कि यह हिंदू–मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए रामबाण सिद्ध होगा और 2024 में बीजेपी की नैया पार लगा देगा। लेकिन कुछ उल्टा ही हो रहा है। इसने सारे विरोधी दलों को एक कर दिया है। देश के बाहर हमारे मित्र राष्ट्र भी इसके विरुद्ध बोलने से नहीं चूक रहे। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन भारत का विरोध करने पर मजबूर हो रहे हैं। बांग्लादेश जैसा भारत का परम मित्र–राष्ट्र भी इस मामले में पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखने लगा है। इमरान खान को मोदी ने नया शिगूफा थमा दिया है। इससे भारत की आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय छवि तो विकृत हो ही रही है, देश में चल रहे हंगामे के कारण संसद और सरकार आर्थिक संकट पर समुचित ध्यान नहीं दे पा रही है। जरूरी यह है कि इस कानून में सरकार समुचित संशोधन शीघ्र करे और अपना ध्यान आर्थिक समस्याओं को हल करने पर लगाए, वरना यही हालत चलती रही तो देश को कहीं दूसरे आपात काल का सामना न करना पड़ जाए।